



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 2016/आश्विन 21, 1938

No. 328]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2016/ASVINA 21, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2016

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सल्फोनेटेड नेपथलीन फारमलिडहाइड” (एसएनएफ) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

सं. 14/15/2016-डीजीएडी.—मै. हिमाद्री स्पेशियलिटी कैमिकल लि. (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष निर्यातित “सल्फोनेटेड नेपथलीन फारमलिडहाइड” (एसएनएफ) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। संबंधित देश चीन जन. गण. है। उपर्युक्त देश को संबद्ध देश भी कहा गया है।

2. और यतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि

कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह याचिका मै. हिमाद्रि स्पेशियलिटी कैमिकल लि. द्वारा दायर की गई है। भारत में संबद्ध वस्तु के अन्य उत्पादक हैं जो एसएनएफ का उत्पादन करते हैं अर्थात् मंगलोर कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (एमसीएफ), एलआरएसी स्पेशियलिटी कैमिकल्स प्रा. लि., गुजरात पालीबेंड्स प्रा. लि., गुजरात पालीसोल कैमिकल्स प्रा. लि., एचआर जोनसन (इंडिया)। मंगलोर कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (एमसीएफ) ने इस याचिका का समर्थन किया है। याचिकाकर्ता कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित नहीं है और याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि याचिकाकर्ता को नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए।

4. प्राधिकारी मानते हैं कि समर्थक घरेलू उत्पादक के साथ याचिकाकर्ता संबंधित नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

5. विचाराधीन उत्पाद निर्यातित "सल्फोनेटेड नेप्थलीन फारमलिडहाइड" (एसएनएफ) है।

6. "सल्फोनेटेड नेप्थलीन फारमलिडहाइड" नेप्थलीन का व्युत्पन्न उत्पाद है। "सल्फोनेटेड नेप्थलीन फारमलिडहाइड" (एसएनएफ) कंडेनसेट का प्रयोग कंक्रीट के लिए निर्माण उद्योग में वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सर के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग रबड़ रसायनों, जिप्सम उद्योगों और विशेष कृषि-रसायन उद्योगों के लिए डिस्पर्सेंट के रूप में भी किया जाता है। एसएनएफ नेप्थलीन के सल्फोनेशन और कास्टिक सोडा द्वारा प्रक्रिया को निष्क्रिय करने बनाया जाता है। यह 100 प्रतिशत पाउडर रूप में और द्रव रूप में 40-45 प्रतिशत ठोस मात्रा की रेंज में उत्पादित किया जाता है।

7. "सल्फोनेटेड नेप्थलीन फारमलिडहाइड" का प्रयोग कंक्रीट एडमिक्सर, के उत्पादन, टैनिंग उद्योग, चमड़ा सहायक सामग्री, वस्त्र अनुषंगी, वैट डाइज, सुपीरियर गुणवत्ता की डिस्पर्स डाइज, कृषि डिस्पर्सेंट विनिमर्तियों, रबड़ और लेटेक्स इमल्सन में किया जाता है।

8. "सल्फोनेटेड नेप्थलीन फारमलिडहाइड" को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के उपशीर्ष 3824 40 90 के अधीन अध्याय 38 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और और प्रस्तावित जाँच और प्रस्तावित उपायों के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना

जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

शामिल देश

10. वर्तमान जांच चीन जन. गण. (जिसे 'संबद्ध देश' भी कहा गया है) से सल्फोनेटेड नेपथलीन फारमल्डिहाइड (एसएनएफ) के कथित पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य

चीन

11. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन के संबंध में नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अधीन कार्य कर रहे हैं। उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और चीन जन. गण. में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

निर्यात कीमत

12. आवेदक द्वारा कारखाना द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण एक गौण स्रोत आईबीआईएस से प्राप्त सौदा-वार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है और समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़े, बैंक प्रभार, कमीशन और वैट समायोजनों साक्ष्य और आधार प्रदान किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जो संबद्ध देश द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में भारी पाटन मार्जिन को दर्शाती है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

14. याचिकाकर्ता ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की बड़ी हुई मात्रा, कीमत ह्रास, कम कीमत पर बिक्री, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय और नकद प्रवाह के अनुसार प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देश से कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

जांच अवधि (पीओआई)

15. वर्तमान जाँच के लिए जांच अवधि अप्रैल 2015 – मार्च 2016 (12 महीनों) की है। क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 12 से मार्च 13, अप्रैल 2013- मार्च 2014, अप्रैल 2014- मार्च 2015, और जांच अवधि को शामिल करने पर विचार और उसका प्रस्ताव किया गया है।

सूचना प्रस्तुत करना

16. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना

प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
चौथा तल , जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

18. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।

21. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

22. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

26. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2016

Subject: Anti-Dumping investigation concerning imports of “Sulphonated Naphthalene Formaldehyde” (SNF) originating in or exported from China PR.

No. 14/15/2016-DGAD.—M/s Himadri Speciality Chemical Ltd. (hereinafter referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of Sulphonated Naphthalene Formaldehyde (SNF) (also referred to as Subject goods). The Country concern is China PR. The above mentioned country also referred to as the Subject Country.

2. And whereas, the Authority notes that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, ‘injury’ to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and ‘injury’ exists justifying initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to consider recommending an amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The petition has been filed by M/s Himadri Specilaty Chemical Limited. There are other producers of the subject goods in India namely Mangalore Chemicals and Fertilisers Ltd (MCF), LRC Specialty Chemicals Pvt. Ltd., Gujarat Polybands Pvt. Ltd., Gujarat Polysol Chemicals Pvt. Ltd., HR Johnson (India) produce SNF. The petition has been supported by Mangalore Chemicals and Fertilisers Ltd (MCF). The petitioner is not related to the exporters or importers of the alleged dumped article and the petitioner has not imported the product under consideration from subject countries. The facts of the case, clearly establish that petitioner should be considered eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

4. The Authority holds that the petitioner along with supporting domestic producer constitutes an eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b) and satisfies the criteria of standing also in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

5. The product under consideration is "Sulphonated Naphthalene Formaldehyde (SNF)".

6. Sulphonated Naphthalene Formaldehyde is a derivative of Naphthalene. Sulphonated Naphthalene Formaldehyde (SNF) Condensate is used as a water reducing admixture in construction industries for concrete. It is also used as dispersant for rubber chemicals, gypsum industries and specialty agro-chemicals industries. SNF is made from sulphonation of naphthalene and neutralization of the process by caustic soda. It is produced in 100% powder form and in liquid form in the range of solid content from 40% - 45%.

7. Sulphonated Naphthalene Formaldehyde is used for the production of concrete admixtures, application in tanning industry, leather auxiliaries, textile auxiliaries, vat dyes, superior quality disperse dyes, agro dispersant formulations, rubber and latex emulsion.

8. Sulphonated Naphthalene Formaldehyde is classified under Chapter 38 of the Customs Tariff Act under customs subheading 3824 40 90. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the proposed investigation and proposed measures.

Like Article

9. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject country and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The applicant has further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the domestic industry in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Countries involved

10. The present investigation is in respect of alleged dumping of Sulphonated Naphthalene Formaldehyde (SNF) from China PR. (referred to as the "subject country").

Normal Value**China**

11. Applicant has claimed that China should be treated as a non-market economy and normal value in case of China should be determined in accordance with para-7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the

subject goods in China PR are operating under non market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

Export Price

12. The applicant has determined ex-factory export price on the basis of transaction wise import data procured from IBIS a secondary source and providing evidence and basis of adjustments on account of ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, bank charges, commission and VAT adjustment.

Dumping Margin

13. The comparison of normal values with the ex-factory export price has been carried out, which shows a significant dumping margin in respect of the subject goods exported by the subject country.

Injury and Causal Link

14. The petitioner has furnished evidence regarding injury due to alleged dumping due to increased imports in absolute terms and relative to production and consumption in India, price depression, price underselling and adverse impact on profitability, return on capital employed, and cash flow of the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by alleged dumped imports from the subject countries to justify initiation of an antidumping Investigation.

Period of Investigation (POI)

15. The period of investigation for the present investigation is from April 2015 – March 2016 (12 Months). The injury investigation period has been considered and proposed to cover the periods Apr'12-Mar'13, Apr'13-Mar'14, Apr'14-Mar'15 and the period of investigation.

Submission of information

16. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, Ministry of Commerce
& Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street, New Delhi -
110001.

17. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

18. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the Interested parties.

22. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such Information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

26. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority